

सीएम हेल्पलाइन का संविदा कर्मी साथी समेत गिरफ्तार

शिकायत का निस्तारण की कराने को लेकर शिकायतकर्ता से मांगी थी 2500 रुपये रिश्वत

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल के संविदा कर्मचारी को पुलिस उसके साथी समेत ढाई हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़ा है। आरोपी हरिद्वार निवासी एक व्यक्ति की शिकायत का निस्तारण करने के लिए यह रकम मांग रहे थे। इसके लिए संविदा कर्मचारी ने अपने खाते का क्यूआर कोड भी पीड़ित के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर भी शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद उन्हें शैलेंद्र गुसाई नाम के व्यक्ति ने खुद को सीएम हेल्पलाइन का कर्मचारी बताते हुए कॉल की। उसने कहा कि उनकी शिकायत का निस्तारण हो जाएगा लेकिन इसके लिए 2500 रुपये देने होंगे। शैलेंद्र ने मनोज ठकराल को

लिए एसओजी को जिम्मेदारी दी गई थी। पता चला कि मनोज ठकराल हरिद्वार के गुरुकृत नारसन में एक रेस्टोरेंट में मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। लेकिन, रेस्टोरेंट संचालक ने मनोज का तय वेतन नहीं दिया। इस पर उन्होंने श्रमायुक्त कार्यालय रुडकी में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन, कोई कर्वाई न होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में संविदा पर तैयार हुए। उसने शैलेंद्र गुसाई को मनोज ठकराल का मोबाइल नंबर भेजा था। ताकि वह उससे बात कर रिश्वत मांग सके। एसएसपी ने बताया कि इस मामले में सब इंस्पेक्टर आदित्य सैनी की तहरीर के आधार पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इस बात की भी जानकारी कर रही है कि कहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ तो इस

तरह की ठारी नहीं हुई है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। शुभम आनंद मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में गत छह महीने से काम रहा है। वह इस वक्त कस्टमर केरेय एजीक्यूटिव के पद पर है। उसका वेतन 10500 रुपये प्रति माह है। शुभम आनंद माउंट व्यू कॉलेजी आईटी पार्क का रहने वाला है। जबकि, उसका साथी शैलेंद्र गुसाई कैनाल रोड, गुमानीवाला, उत्तराखण्ड के प्रापौर्णी डीलिंग का काम करता है। आरोपियों ने कुछ समय पहले इस तरह की योजना बनाई थी। एसएसपी ने अपील की है कि यदि किसी ने इस प्रकार से रिश्वत दी है तो वह भी पुलिस को शिकायत कर सकता है।

अवैध शराब की सप्लाई का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

हरियाणा की शराब पर उत्तराखण्ड का मोनोग्राम लगाकर गोदाम से करते थे सप्लाई

देहरादून(उद संवाददाता)। हरियाणा

की शराब पर उत्तराखण्ड के मोनोग्राम और लेबल लगाकर बेचने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक गोदाम

और वाहन भी पकड़ा है, जिससे बड़ी मात्रा में हरियाणा की शराब बरामद हुई है। तीनों आरोपी बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गोदाम से हजारों मोनोग्राम, स्टीकर और अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने सप्लाई के लिए प्रयोग किए जा रहे वाहन के भी सीज किया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कर्वाई नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में की गई। एसओ नेहरू कॉलोनी मोहन सिंह की टीम ने यूटीलिटी वाहन पकड़ा था। इसमें देखा तो पता चला कि शराब की 15 पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद हुई थीं। यह शराब हरियाणा में बिक्री वाली थी। चालक से पूछताछ हुई। एसएसपी ने बताया कि तीनों



पेटियां अंग्रेजी शराब की बरामद हुईं। साथ ही उत्तराखण्ड आबकारी के मोनोग्राम, शराब के स्टीकर व अन्य सामग्री बरामद हुईं। एसएसपी ने बताया कि तीनों

किया गया है। आरोपी यहां सस्ती शराब लाकर इस पर उत्तराखण्ड का स्टीकर लगाकर बेचते थे। इससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे थे। इनके अन्य

शराब उत्तराखण्ड की ही हुई।

श्री दुर्गा समिति द्वारा मां वैष्णो दरबार यात्रा 24 सितम्बर से

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। श्री दुर्गा समिति के तत्वाधान में श्री दुर्गा मंदिर से इस बार 33 वीं मां वैष्णो दरबार यात्रा आगामी 24 सितम्बर को प्रस्थान करेगी। वरिष्ठ समाजसेवी एवं यात्रा समिति के

से ले जाता है उनकी बस चढ़ जाती है। अब वेद को माँ नैनादेवी जी से मिलने का जूनून सवार हो गया। उन्होंने मंदिर की तरफ देखकर अरदास लगाई। रात को माँ नैनादेवी सपने में आयी और बस लाने



संयोजक वेद दुकराल के नेतृत्व में यात्रा का आदेश दिया। अगले दिन जब चिंतपूर्णी जी से वापिस आ रहे थे तो फिर नैनादेवी जी का मंदिर दिखाई दिया। तब वेद दुकराल ने बस में घोषणा की, अगले साल एक बस माँ वैष्णो दरबार यात्रा पर आएंगी जो सबसे पहले नैनादेवी जी के दर्शन करेगी। बस में कई लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया। लेकिन माँ

भगवती के आशीर्वाद की बस 33 वर्ष में प्रवेश कर, हजारों लोगों को दर्शन करा चुकी है। इस बस में सबको सभी स्थानों पर खुले दर्शन होते हैं, चाहे कितनी भी

भीड़ क्यों न हो। वेद दुकराल ने बताया कि बस में सभी देवता विराजमान रहते हैं और यात्रा की समाप्ति पर होने वाले हवन में आशीर्वाद देकर जाते हैं।

शक्तिफार्म मार्ग पर नो इन्ट्री की मांग

शक्तिफार्म (उद संवाददाता)। शक्तिफार्म के लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर सिड्कुल से शक्तिफार्म होकर गुजराने वाले वाहनों पर सुबह पाँच से रात दस बजे तक रोक लगाने की मांग की है। शक्तिफार्म के वार्ड नं. ३० दरियासी रमेश राय ने एसएसपी पत्र देकर कहा है कि कुछ समय पहले हारसे में एकात्र और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई थी।

इसके बाद शक्तिफार्म पुलिस ने गणमान्य लोगों के साथ बैठक कर कस्बे में बड़े वाहनों के लिए सुबह पाँच से लेकर रात दस बजे तक नो एंट्री लागू करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय का तीन महीने तक पालन किया गया। जिससे हादसा में कमी आई।

इसके बाद इसका पालन बंद कर दिया गया है। अब दिन रात सिड्कुल से निकलने वाले बड़े वाहन शक्ति

फार्म होकर किंच्चा की ओर जाते हैं। इस मामले की शिकायत एसडीएम से करने पर उन्होंने कई बार पुलिस को नो एंट्री का पालन करने का आदेश दिया लेकिन अब तक व्यवस्था लागू नहीं की गई। उन्होंने एसएसपी से नो एंट्री लागू करने की मांग की है। ज्ञान देने वालों में रमेश रॉय, विश्वजीत विश्वास, रंजीत सरकार, समीर शील, दिलीप रॉय व मनोज महंत आदि शामिल थे



का आदेश दिया। अगले दिन जब चिंतपूर्णी जी से वापिस आ रहे थे तो फिर नैनादेवी जी का मंदिर दिखाई दिया। तब वेद दुकराल ने बस में घोषणा की, अगले साल एक बस माँ वैष्णो दरबार यात्रा पर आएंगी जो सबसे पहले नैनादेवी जी के दर्शन करेगी। बस में कई लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया। लेकिन माँ

उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के सेवन से शरीर को जहां मजबूती प्रदान होती है वहीं बैद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। कार्यक्रम की

अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के विभाग प्रभारी डॉ. पीएन तिवारी द्वारा एवं संचालन गृह विज्ञान विभाग प्रभारी डॉ. पारूल बोरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉ.

नीतिका, डॉ. निर्मला जोशी, डॉ. राहुल चंद्रा, डॉ. दीपाली कनवाल, डॉ. अस्था अधिकारी, डॉ. निष्ठा शर्मा, डॉ. किसन चौहान आदि प्राध्यापक सम्मिलित हुए।

बेहतर होता है विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों को मोटे अनाज का अधिकतम सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं।



शिमला में हिमाचल प्रदेश के

अधिकारियों से मिले राज्यपाल

देहरादून (उद संवाददाता)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि)

ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों से औद्योगिकी (बागवानी) और आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रयासों की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों ने आपदा से निपटने के लिए प्रबंधावारी रणनीतियों, किसानों की आय में वृद्धि हेतु सेवा और अन्य फलों की खेती को प्रोत्साहित करने और जैविक एवं प्रकृतिकृषि में हो रहे नवाचारों पर



प्रस्तुतीकरण दिया। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का सेव उत्पादन पूरे देश में एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित हुआ है। उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश की समान भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस मॉडल को उत्तराखण्ड में भी अपनाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। राज्यपाल द्वारा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में दोनों प्रदेशों के बीच आपसी सहयोग और समर्क्य बढ़ावे पर जोर दिया गया।

</

अपहरण, चोरी, वाहन चोरी, लूट की घटनाओं में हुई बढ़ोत्तरी

उत्तराखण्ड में तीन वर्षों में हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे अपराधों में आयी कमी

काशीपुर (उद संवाददाता)। अपने पत्रांक 53 के साथ पुलिस उपाधीकक सी.सी.टी.एन.एस. विकेंक सिंह कुटियाल द्वारा उपलब्ध कराये गये वर्ष 2021, 2022 व 2023 के अपराधों के विवरण की सत्यापित फोटो प्रति उपलब्ध करायी है। श्री नदीम को उपलब्ध 2021, 2022 तथा 2023 तीन वर्ष के तुलनात्मक अपराधों के विवरण करायी गयी सूचना से हुआ। काशीपुर के अनुसार उत्तराखण्ड में 2021 में 208 हत्या के अपराध हुये थे जो 2022 में 187 तथा 2023 में 12 प्रतिशत कम होकर 183 हो गये। दहेज हत्या के वर्ष 2021 में 72 अपराध हुये जबकि 2022 में 70 तथा 2023 में 33 प्रतिशत कम होकर 48 हो गये। हत्या के लिये अपहरण के 2021 में 4 अपराध, 2022 में 2 तथा 2023 में 75 प्रतिशत कम



होकर 1 रह गये। फिरौती के लिये 867 हो गये लेकिन 2023 में 2021 के अपहरण के 2021 में 6, वर्ष 2022 में 3 तथा 2023 में 66 प्रतिशत कम होकर 421 अपराध ही रह गये। डकैती के 2021 में 14 अपराध हुये जो 2022 में 35 प्रतिशत बढ़कर 19 हो गये लेकिन 2023 में 21 प्रतिशत कम होकर 11 रह गये। आई.

टी.एक्ट के 2021 में 668 अपराध हुये जो 2022 में 495 तथा 2023 में 38 प्रतिशत कम होकर 417 रहे गये। अन्य आई.पी.सी. अपराधों में भी भारी कमी हुई है। 2021 में 4145 अपराध दर्ज हुये जो 23 प्रतिशत घटकर 2022 में 3204 रह गये हैं तथा 2023 में वर्ष 2021 की तुलना में 40 प्रतिशत कम होकर 2503 रह गये हैं। श्री नदीम को उपलब्ध विवरण के अनुसार विभिन्न अपराधों में 2021 की तुलना में बढ़ोत्तरी भी हुये हैं। इसमें अपहरण के 2021 में 819 अपराध हुये जो 2022 में 43 प्रतिशत बढ़ोत्तरी होकर 1169 हो गये तथा 2023 में 2021 की तुलना में 54 प्रतिशत बढ़कर 1264 हो गये। दांडों के 2021 में 791 अपराध हुये जिसमें 2022 में 16 प्रतिशत अधिक 195 अपराध हुये हैं।

एसएसपी ने किया महिला हेल्प लाईन का औचक निरीक्षण

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने महिला हेल्प लाईन का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने सख्त दिशा निर्देश दिया है। शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिलाओं से संवर्धित अपराधों में पीड़ितों की तत्काल सहायता करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस कार्यालय में रुद्रपुर रेलवे ट्रैक पर लोहे का पोल रखने के साथ घटनास्थल का दौरा कर जानकारी हासिल की। उन्होंने कार्मिकों को रेलवे ट्रैक की निरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। इसकी जांच रामपुर (यूपी) पुलिस को सौंप दी गई है। शुक्रवार रात रुद्रपुर सिटी स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर यूपी सीमा पर स्थित बिलासपुर क्षेत्र में अवांछनीय तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर लोहे का पोल रख दिया था। इसी ट्रैक से रात साढ़े नौ बजे देहरादून से काठगोदाम जाने वाली नैनी-दून जन शताब्दी ट्रेन को गुजरना था। समय रहते लोकों पायलट ने ट्रैक पर पोल देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। मामला सामने आने के बाद रेलवे कर्मचारी को निर्देशित किया गया की प्रश्नासन में हड्डकंप मच गया। रेल सुक्ष्म बल (आरपीएफ) सक्रिय हो गई। शुक्रवार को रेलवे के इंजन नगर (बरेली) मंडल के कमांडेंट पवन कुमार



आरपीएफ कर्मियों ने उन्हें बताया कि रेलवे पटरी के पास टेलीफोन का खंबा काफी समय से पड़ा था। इसे उठाकर पटरी पर रखा गया था। श्रीवास्तव का

कहना था कि मामला रामपुर (यूपी) पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ही इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। उधर, पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि रेलवे ट्रैक को बाधित करने के मामले के खुलासे में आरपीएफ रामपुर पुलिस को सहयोग कर रही है। जल्द ही प्रकरण से पर्दा उठने की उमीद है। पवन कुमार श्रीवास्तव, कमांडेंट आरपीएफ के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि ट्रेन को आरपीएफ कर्मियों ने उन्हें बताया कि रेलवे पटरी के पास टेलीफोन का खंबा नहीं सकती है। फिर भी सारे पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।

महिला की मौत के मामले में पति सहित चार पर केस दर्ज

गदरपुर (उद संवाददाता) क्षेत्र के एक निकतवर्ती ग्राम पिपलिया में एक विवाहिता की सर्दियां परिस्थितियों में मौत के मामले परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर समुखल पक्ष के चार लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को मनोरंजन बैराणी पुत्र अल्लाद बैराणी निवासी चितरंजनपुर अपने कई नाते रिश्तेदारों के साथ थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने करीब दो साल पूर्व अपने सामर्थ के अनुसार अपनी पुत्री ममता बैराणी का विवाह ग्राम पिपलिया न 01 निवासी गोतम से किया था। उन्होंने बताया कि विवाह के कुछ समय बाद तो सब ठीक ठाक रहा लेकिन जैसे समय बीता तो समुखल वाले दहेज की मांग करते हुए पुत्री को प्रताड़ित करने लगे जबकि कई बार पैंचायत भी हुईं और गढ़मान्य लोगों के समझाने पर सुलह हो गई लेकिन फिर पुत्री के साथ आए दिन मारपीट करते हुए दहेज की मांग होने लगी। उन्होंने बताया कि गुरुवार की देर रात दामाद गैतम ने उन्हें फोन कर ममता की जिला चिकित्सालय में मौत होने की सूचना दी सूचना मिलने के बाद जब वह जिला अस्पताल पहुंचे तो उनकी पुत्री ममता के मुंह में से झाग निकल रहे थे और जहरीली दिवाने जौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर समुखल पक्ष के चार लोगों पर बोनेन्स धारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3, दहेज प्रतिवंश अधिनियम 4 वह बीनन्स की धारा 80 (2) के तहत पति, सास, देवर और नंद पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस पर निकलेगी शोभायात्रा

किंचा। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के बैनर तले राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में आगामी महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाने हेतु सर्पंच राकेश कुमार वाल्मीकि की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें 16 अक्टूबर को पुरानी गल्ला मंडी से शोभायात्रा निकालने व 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि पार्क में दीप प्रज्वलित कर राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में भंडारा करने का निर्णय



लिया गया इस मौके पर सर्वसम्मति से कार्यक्रम का अध्यक्ष नितिन चरन बाल्मीकि को चुना गया इस मौके पर चौथी ईशा चरन, कल्लू चरन, कैलाश वाल्मीकि, विनोद कुमार आकाश वाल्मीकि, माइकल, सूरज वाल्मीकि, विमल चरन, राजेश वाल्मीकि, राजेंद्र कुमार, अक्षय रावत, शिवम वाल्मीकि, अरुण वाल्मीकि, सचिन चरन, राकेश भारती, राजू, सुमित, संजय कुमार, निवास बाबू, राजीव सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।

व्यायाम अंग्रेजी दवाईयां आपका दोगा ठीक करने में नाकाम हैं तो मिलें— विजय आयुर्वेद एंटरप्रार्सेस

निम्न दोगों के इलाज में 16 वर्षों का अनुभव:-

पार्किंसन, अल्जाइमर, मानसिक विकार, निःस्वास आंखों की कमी आदि। डिस्ट्रोफिक प्रोलेप्स सर्वाइकल, गठिया, घुटने का दर्द, किडनी रोग (डायलिसिस से पहले)

लीकर सिरोसिस, हैपेटाइटिस B&C, Fatty Liver प्रोस्टेट रोग असाध्य एवं लाइलाज रोगियों की विकित्सा शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा की जाती है।

DR. VIJAY PRAKASH MISHRA M.D. (Ayurveda)
Mob.: 9410897970

DR. ASHWINI MISHRA M.D. (Ayurveda)
स्त्री एवं त्वचा रोग

मिलन का समय : प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक (शुक्रवार अवकाश)

होटल राजश्री के सामने, गल्ली नं. 2, डॉक्टर्स कालेजी डी. १२ सिविल लाईन, रुद्रपुर (उत्तराखण्ड)

काशीपुर (उद संवाददाता)। शहर में प्रोफेशनल डोनर्स का एक बड़ा रेकेट सक्रिय है। खून के खुनी खेल में गिरोह तथा उसके तंत्र सक्रिय है। गिरोह के गुर्गे ब्लड डोनेट करने वालों को कमियां गिनाकर डरा देते हैं। रक्तदान के नुकसान गिनाकर उन्हें गुमराह किया जाता है इससे डोनर डर भाग जाता है। ऐसे में ब्लड बैंक में खून के रहने हुए गोरियों को समय पर करते हुए रक्तदान के नुकसान गिनाकर उन्हें गुमराह किया जाता है इससे डोनर डर भाग जाता है। ऐसे में ब्लड बैंक में खून के रहने हुए गोरियों को समय पर रक्त नहीं मिल पाता और इसी का पूरा फायदा तथा कथित ब्लड बैंक के संचालक उत्तर रहे हैं। दलाल मरीजों को विश्वास में लेकर प्रोफेशनल रक्तदान से मनमानी रेट पर खून उपलब्ध करा देते हैं जिससे मोटी कमाई हो रही है। ओपीडी समाप्त होने के बाद से देर रात खून का यह खूनी खेल चल रहा है। कहने को राजकीय चिकित्सालय परिसर में ब्लड बैंक में लेकिन अक्सर रोगियों के तिमारदारों को खून देने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। सूत्रों का कहना है

अधिकांश पैथोलॉजी में खून का गंदा खेल खेला जा रहा है। पैथोलॉजी से सीधे प्राइवेट अस्पतालों में खून की स्पलाई दी जा रही है। खून सही है या सक्रियत मरीजों को यह भी पता नहीं चल पाता।

समीप स्थित एक ब्लड बैंक इन दिनों इस तरह के अजब गजब कारनामों को लेकर खासा स

उत्तराखण्ड में हो रहा चहुंमुखी विकास : अजय टम्टा

केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने सरकार के सौ दिन पूर्ण होने पर दी विकास योजनाओं की जानकारी

नैनीताल (उद संवाददाता)। केन्द्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस काठगोदाम में सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता कर केन्द्र सरकार द्वारा आमजननामनस के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे विस्तृत जानकारी दी। श्री टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के 100 दिन पूरे होने पर सामाजिक ढाँचे पूर्ण करने हेतु 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के निवेश पूर्ण कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा - बागेश्वर रोड में लगभग 4.50 करोड़ के पहले पैकेज का काम शुरू किया है साथ ही काठगोदाम से नैनीताल को टूलें करने का रहा है तथा ज्योलिकट से भवाली कैची बाईपास होते हुए अल्मोड़ा से गानीखेत पाड़खोला होते हुए कर्णप्रयाग तक तथा अल्मोड़ा से पनार तक टूलें किया जायेगा। वही धारान्कुला से गुंजी तक टूलें लगभग उत्तराखण्ड की सभी लक्ष्य दिसंबर 2024 तक लगभग 384.00 करोड़ की लागत की डीपीआर 09.07.2024 को अवार्ड कर दिया गया है। जिससे लिपुलेख से माउंट कैलाश के दर्शन सुगम हो जायेंगे। चीन बैंडर की सीमावर्ती कर्नेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा इसके अलावा वहा सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। कार्य के निर्माण की अवधि 2 वर्ष रखी गयी है। चारधाम एनएच की रोड का टूलें किया जाना है। श्री टम्टा ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-09 के 58 किलोमीटर में एक लेन/इंटरमीडिएट लेन से दो लेन चौड़ीकरण का कार्य रु 307.00 करोड़ लागत की डीपीआर 10.07.2024 को इस कार्य की स्वीकृति मिली है। इससे चम्पवात शहर में यातायात भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। कार्य की स्वीकृति का लक्ष्य दिसंबर 2024 रखा गया है। चारधाम परियोजना के अन्तर्गत ऋषिकेश बाईपास चार लेन 10.88 किलोमीटर लम्बाई में रु 1414 करोड़ लागत की डीपीआर प्रगति में है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित ओवरसाइट समिति द्वारा दिनांक 10.07.2024 को इस कार्य की स्वीकृति मिली है। इससे ऋषिकेश शहर एवं चारधाम यात्रियों को यातायात भीड़भाड़ से राहत मिलेगी। कार्य की स्वीकृति का लक्ष्य दिसंबर 2004 रखा गया है। चारधाम मार्ग पर हो रहे भूखलन क्षेत्रों के उपचार कार्य अवार्ड किये जा चुके हैं। कार्य पूर्ण करने की अवधि 12 माह से 18 माह रखी गई है। मोदी सरकार के तीसरे

कार्यकाल के पहले 100 दिनों में, कुल 15 लाख करोड़ के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका उद्देश्य कृषि, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को मजबूत करना है। पीएम किसान निधि के 17वीं किश्त के तहत 9, 3 करोड़ से अधिक किसानों को 220,000 करोड़ वितरित किए गए, जिससे किसानों की वित्ती स्थिति में सुधार हुआ है। सत्र

की गई है और तीन प्रमुख कैंसर दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी गई। सड़क, रेल, बांदरगाह और हवाई मार्गों की कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रु 3 लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सामाजिक कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000

कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत फेशन की गारंटी दी गई है और वन रैक वन पेंशन (ओआर ओपी) योजना का पुनरीक्षण किया गया है। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ४ लाख करोड़ की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सामाजिक कल्याण के लिए, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000

उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान में बड़ीपास और सड़कों का विस्तार शामिल है। इसके अलावा, 219 किमी हाई-स्पीड कॉरिडोर संचालन के लिए तैयार हैं, जिससे देश में हाई-स्पीड कॉरिडोर की कुल लंबाई 2,357 किमी हो गई है। ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) के तहत बैरियर-फ्री योलिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने 100 दिनों के कार्यकाल में ४ प्रमुख हाई-स्पीड कॉरिडोर और रिंग रोड परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनमें आगरा-ग्वालियर, खरगोपुर-मोरेग्राम, धराड़ मेहसाणा-अहमदाबाद, अयोध्या-रिंग रोड, पाथलगांव-गुमला, कानपुर-रिंग रोड, गुवाहाटी-रिंग रोड और नासिक फाटा-खेड़ एलिवेंट कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक की कमी आएगी, ट्रैफिक की क्षमता में वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। साथ ही, इनका उद्देश्य कुल मिलाकर ४०५ करोड़ से अधिक मानव-दिनों का रोजगार सृजन करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इन परियोजनाओं से देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा समय में ५० प्रतिशत से ६० प्रतिशत

जनसाधिकी बदलाव पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाये जायें: उदयराज

डीएम ने दिए महिला सुरक्षा हेतु जिला स्तर पर एसओपी तैयार करने के निर्देश

रुद्रपुर(उद संवाददाता)। जनपद में अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा। उन्होंने परगना स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस उपाधीकक सहित तीन महिला अधिकारियों को रखते

राजस्व, वन, नज़ूल, सड़क किनारे भूमि पर अवैध अतिक्रमण को सख्ताई से रोकने के निर्देश वनाधिकारियों

उन्होंने वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को सख्ताई से रोकने के निर्देश वनाधिकारियों

तथा समस्याओं का निराकरण करते हुए

दो लोगों के जीवन को रोशन करेंगी परमजीत कौर की आंखें

गदरपुर(उद संवाददाता)। समाजसेवी रविन्द्र सिंह बजाज की माता श्री मति

परमजीत कौर पत्नी श्री सरदार जगतार सिंह निवासी सरस्वती कालोनी गदरपुर का आक्रिमिक निधन हो गया। दुख की घड़ी में उनके पुत्र रविन्द्र सिंह बजाज द्वारा माता

जी की इच्छानुसार नेत्रदान हेतु सोचो डिफरेंट संस्था से संपर्क किया। तत्पश्चात

महाराजा अग्रसेन ग्लोबल चैरिटेबल ट्रस्ट

द्वारा संचालित सी आर मित्तल नेत्रदान केंद्र,

रुद्रपुर की टीम के द्वारा केंद्र निदेशक डॉक्टर

एल एम उप्रेती की देखरेख में श्री मनीष

रावत नेत्रदान टेक्नीशियन एवं श्री सत्येंद्र

मिश्र द्वारा नेत्रदान कराया गया। इस अवसर

पर श्री अंश दीप सिंह, मनमीत सिंह,

तरनजीत सिंह हैरी, श्री तजेंद्र सिंह, श्रीमती

जगजीत कौर ललित पांडे, आदि परिजन

उपस्थित रहे। गदरपुर नगर के दो युवा

जिन्होंने नेत्रदान के क्षेत्र में लोगों को जारूर करने का बीड़ा उठाया और एक विकास

भूमियों पर्वत में फरीदाबाद में आईसीआईसीआई बैंक में मैनेजर थे। पद छोड़

समाज सेवा के जुनून को लेकर अपने ग्रह क्षेत्र में आए वही दुसरी और नगर के

ब्लड मैन के नाम से प्रसिद्ध युवा समाज सेवी संदर्भ प्राविष्ठा वाला है। दोनों ही बचपन

के दोस्त हैं और दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिनका नाम रखा सोचो डिफरेंट।

जिसका मकसद समाज को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना है। वह क्षेत्र में जीते

जी रक्तदान मरणोपरांत नेत्रदान की मुहिम को साकार करने में लगे हुए है।



को दिए। जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष प्रयास की आवश्यकता पर बल देते हुए

हुए समिति गठित करने के निर्देश दिए। गठित समिति समय समय पर अपने क्षेत्र में कार्यालयों, उद्योगों एवं निजी संस्थानों का भ्रमण कर महिला कर्मचारियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं से वाकिफ होंगे।

डॉ. पंकज शुक्ल, एसडीएम कौस्तुभ

मिश्र, आसी कले, गौरव पांडे, डॉ. अमृता

शर्मा, तहसीलदार दिनेश कुटोला, गिरीश

जोशी उपस्थित थे तथा प्रभागीय

वनाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।



पानी में बह गया था। उन्होंने कहा कि यह घटना दूसरी बार है जब 11 साल में पुल का संपर्क मार्ग टूटा है। रेलवे क्रांतिकारी एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए

तैयार हुआ। इसके बाद अक्टूबर 2021 और अब 14 सितंबर को इसका संपर्क मार्ग बह गया। ज्ञापन में सरकार से मार्ग की गई है कि शीघ्र गैलापुल का मजबूत तरीके से निर्माण कार्य करवाया जायें जिससे आवाजाही सुचारू रूप से चल सके। वह अंतर्राष्ट्रीय स्टेंडियम समेत कई शहरों वह गांवों को भी जोड़ता है। कार्य न होने पर उग्र अंदोलन करने को बाध्य होना

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रशिक्षण योजना की प्रथम वर्षगांठ समारोह वर्धा, महाराष्ट्र में आयोजित किया और एनएसटीआई हल्द्वानी को इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ने का अवसर मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ हल्द्वानी के निवार्तमान महापौर डॉ. जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। उन्होंने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षणार्थियों

को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉ. अनफल अर्श ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित किया। सभी प्रशिक्षणार्थी तहत संस्थान ने लगभग 120 युवाओं को प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति एनएसटीआई हल्द्वानी के प्रधानाचार्य

नमंत्री विश्वकर्मा प्रशिक्षण योजना के लिए प्रेरित किया। सभी प्रशिक्षणार्थी तहत संस्थान ने लगभग 120 युवाओं को प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

भगत सिंह ने भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर किया। उन्होंने बताया कि यह संस्थान युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर वितरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण अधिकारी सुधीर सिंह, अपर प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

पड़ेगा। ज्ञापन देने वालों में लक्ष्मी नारायण, शशि गुप्ता, लक्ष्मी देवी, प्रमोद अग्निहोत्री, जितेन्द्र सागर, सैयदा मिस्ट्रीकी, मंजू शाह, बेबी गोविल, बर्खा शर्मा, प्रकाश आर्या समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।

हल्द्वाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉ. अनफल अर्श ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि यह संस्थान युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर वितरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण अधिकारी सुधीर सिंह, अपर प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

पर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डीआरडीओ के वैज्ञानिक डॉ. अनफल अर्श ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित किया। सभी प्रशिक्षणार्थी तहत संस्थान ने लगभग 120 युवाओं को प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

भगत सिंह ने भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर

किया। उन्होंने बताया कि यह संस्थान युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने पर वितरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर

प्रशिक्षण अधिकारी सुधीर सिंह, अपर प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

भगत सिंह ने भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर

प्रशिक्षण अधिकारी सुधीर सिंह, अपर प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

भगत सिंह ने भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर

प्रशिक्षण अधिकारी सुधीर सिंह, अपर प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

भगत सिंह ने भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर

प्रशिक्षण अधिकारी सुधीर सिंह, अपर प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

भगत सिंह ने भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर

प्रशिक्षण अधिकारी सुधीर सिंह, अपर प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

भगत सिंह ने भी प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित गोस्वामी ने किया। इस अवसर पर

प्रशिक्षण अधिकारी सुधीर सिंह, अपर प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम का समाप्ति प्रशिक्षण अधिकारी राकेश कुमार

भगत सिंह ने

उत्तरांचल दर्पण

सम्पादकीय

खालिस्तानी अलगाववादी

खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पनू की हत्या की साजिश के आरोप में एक अमेरिकी अदालत के भारत सरकार, राष्ट्रीय सुक्ष्मा सलाहकार और रॉप्रमुख के खिलाफ, जारी अदालती फरमान को लेकर स्वाभाविक ही चर्चा तेज हो गई है। यह चर्चा ऐसे समय में शुरू हो गई है, जब अगले हफ्ते प्रधानमंत्री कवाड़ वैठक में हिस्सा लेने अमेरिका जाने वाले हैं। पनू की हत्या की साजिश का पर्दाफाश खुद अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने किया था। उसने एक भारतीय व्यवसायी को गिरफ्तार किया था, जिसने कबूल किया कि एक बड़े भारतीय अधिकारी के कहने पर उसने पनू की हत्या को साजिश रखी थी। इसे लेकर वहाँ के अखबारों में भी खूब चर्चा रही। उसी आधार पर पनू ने अमेरिका की एक जिला अदालत में मुकदमा दायर किया, जिसके आधार पर यह अदालती फरमान जारी हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने पनू के मुकदमे को निराधार बताया है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने हार्दीप सिंह निजर की हत्या में भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ बताया था। उस संबंध में भारत सरकार लगातार कनाडा सरकार से सबूत मांगती रही, मगर वह दे पाने में अक्षम ही साबित हुई। कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी अदालत के फरमान के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ खातास पैदा हो सकती है, मगर इसका कोई आधार नहीं है। अदालतों की अपनी एक प्रक्रिया होती है और अमेरिकी जिला अदालत ने उसका पालन किया है। इससे अमेरिका और भारत के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। छिपी बात नहीं है कि पनू को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। वह प्रकट रूप से खालिस्तान समर्थकों को उकसाता और मदद मुहैया करता रहता है। वह अमेरिका और कनाडा दोनों देशों का नागरिक है। भारत सरकार उसके खिलाफ शिकंजा कसने की मांग करती रही है, मगर कनाडा सरकार ने कभी उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। जब एक संदिग्ध भारतीय नागरिक को अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया और उससे पता चला कि पनू की हत्या की साजिश रखी गई है, तो पनू को खालिस्तान समर्थकों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने और उनकी सहानुभूति हासिल करने का मौका मिल गया। जाहिर है, इस बहाने वह अपने पक्ष में सहानुभूति लहर बनाने और यह साबित करने का प्रयास कर रहा है कि भारत सरकार खालिस्तान समर्थकों के विरुद्ध साजिशें रच रही है। कोई भी देश और वहाँ की अदालत किसी भी आतंकी गतिविधि में शामिल व्यक्ति के किसी दूसरी सरकार के विरुद्ध अनर्गल आरोप को ग्रोत्साहित नहीं कर सकती। चूंकि अमेरिकी अदालत के सामने पनू के आरोपों के पीछे कुछ आधार हो सकते हैं, इसलिए अदालत ने यह फरमान जारी कर दिया। मगर इसका यह अर्थ कर्दाँ नहीं कि इससे पनू का पक्ष मजबूत हो गया। केवल किसी आरोपी के कबूलनामे के आधार पर कोई मामला सच साबित नहीं हो जाता। ऐसे मामलों में उच्चस्तरीय जांचें महत्वपूर्ण होती हैं। जब अमेरिकी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रहीं, तो पनू के आरोप का बहुत कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के समय भी निश्चय ही इस मामले पर वहाँ के राष्ट्रपति के साथ चर्चा होगी। यह बात गहराइ से रेखांकित होनी चाहिए कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त और अमेरिका तथा कनाडा जैसी जगहों पर पनाह पाए पनू जैसे लोगों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है।

पूंजी निवेश के सभी प्रोजेक्ट की डीपीआर केंद्र को भेजने के निर्देश

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रूढ़ी ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत पूंजी निवेश के सभी प्रोजेक्ट की डीपीआर व प्रस्तावों पर तत्परता से कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विभिन्न जनपदों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की डीपीआर 30 सितम्बर, पर्यटन विभाग को



प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों के विकास से संबंधित लगभग ₹250 करोड़ के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव 15 अक्टूबर, परिवहन विभाग को लगभग ₹100 करोड़ के पुराने वाहनों के स्कैपिंग प्रस्ताव दिसंबर तक प्रेषित करने की डेलाइन दी है। मुख्य सचिव ने उद्योग एवं आवास विभाग को लगभग ₹100 करोड़ के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव 31 अक्टूबर, राजस्व एवं कृषि विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड सम्बन्धित सुधारों व आधुनिकीकरण से सम्बन्धित लगभग ₹505 करोड़ के प्रस्ताव जल्द से जल्द भारत सरकार को प्रेषित करने की डेलाइन दी है। बैठक में सचिव अपर मुख्य सचिव श्री आनंद बद्रन, सचिव श्री दिलीप जावलकर, श्री एस एन पाण्डे, अपर सचिव श्रीमती पूजा गर्वाल, श्री नितिन भद्रैश्या व श्री विजय जोगदण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

नक्सलवाद से निर्णायिक लड़ाई

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का संगठन अब सिमटा दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र को पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए।



गृहमंत्री अमित शाह ने रायगढ़ में कहा है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है और इसे खत्म करने के लिए कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। केंद्र नक्सलवादी वामपंथी उग्रवाद का खात्मा करने के लिए कृत संकलिप्त है। नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी उग्रवाद की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहाँ रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। नई राजनीति के अंतर्गत अब सरकार की कोशिश है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाए, जहाँ नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं। इस नारे इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्रों पर हुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षा बलों के लग पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये इसी अदिवासी बहुल इलाका हैं, जिससे ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुरक्षा सुरक्षाबलों को लग पाना अद्वितीय है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार के विकास इंसानों में जब भी कोई विकास कार्य या चुनाव प्रक्रिया संपन्न होती थी तो नक्सली उसमें रोड़ा अटका देते थे। नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्य व केंद्र सरकार दावा कर रही है कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूटी दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बनायी है कि समस्या पर अकुश विकास की धारा से लग रहा है? क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका बातचीत के लिए राज्य व केंद्र सरकार दावा कर रही है कि समस्या पर अकुश विकास की धारा से लग रहा है? क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे हैं। एक उद्देश्य बोलकर करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूटी दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बनायी है कि समस्या पर अकुश विकास की धारा से लग रहा है? क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे हैं। एक उद्देश्य बोलकर करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूटी दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बनायी है कि समस्या पर अकुश विकास की धारा से लग रहा है? क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रमाण भी मिले हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका लेकिन नतीजे अनुकूल नहीं रहे हैं। एक उद्देश्य बोलकर करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूटी दिख रही है, लेकिन इस

